

बैंकिंग और अर्थव्यवस्था साप्ताहिक एक लाइनर

22nd - 30th अप्रैल 2019



साप्ताहिक वन लाइनर
बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था घटनाक्रम
(22-30 अप्रैल 2019)

प्रिय अभ्यर्थियों,

साप्ताहिक वन लाइनर महत्वपूर्ण बैंकिंग एवं आर्थिक मामलों से जुड़ी खबरों तथा घटनाक्रमों का संग्रह है जोकि (22-30 अप्रैल) 2019 में घटित हुई हैं। यह लेख आगामी सभी बैंकिंग तथा बीमा परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से जुड़ी खबरें

1. RBI ने एनएचबी, नाबार्ड में अपनी पूरी हिस्सेदारी 1,470 करोड़ रुपये में सरकार को बेची

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में अपनी पूरी हिस्सेदारी सरकार को क्रमशः 1,450 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये में बेच दी है।
- इसके बाद ये दोनों कंपनियां पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां बन गई हैं।
- रिज़र्व बैंक ने एनएचबी में 19 मार्च को अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी, जबकि नाबार्ड की हिस्सेदारी 26 फरवरी को ही सरकार को बेच दी गई थी।

नोट:

- राष्ट्रीय आवास बैंक में पूरी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी आरबीआई के पास थी जिसे 19 मार्च 2019 को बेच दिया गया।
- रिज़र्व बैंक ने दूसरी नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इससे पहले स्टेट बैंक, एनएचबी और नाबार्ड में मालिकाना हक सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव अक्टूबर 2001 में कर दिया था।
- केन्द्रीय बैंक के पास नाबार्ड में 72.5 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इसमें से 71.5 प्रतिशत हिस्सेदारी को अक्टूबर 2010 में ही सरकार के सुपुर्द कर दिया गया था, जबकि शेष बची हिस्सेदारी 26 फरवरी 2019 में सरकार को बेची गई।

नोट

- यह कदम दूसरी नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुरूप उठाया गया है। इसमें नियामकीय संस्थानों की एक दूसरे में शेरधारिता को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। यह रिपोर्ट 2001 में सौंपी गई थी। रिज़र्व बैंक के अपने स्तर पर भी इस संबंध में एक परिचर्चा पत्र जारी किया गया था।
- नरसिम्हन समिति ने कहा था कि रिज़र्व बैंक को उन संस्थानों में हिस्सेदारी नहीं रखनी चाहिये जिनका वह नियमन करता है।

नाबार्ड के बारे में

- नाबार्ड सहकारी बैंकों और आरआरबी के कार्यों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।
- हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

एनएचबी के बारे में

- अब NHB, RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नहीं है क्योंकि सरकार इसमें 100% हिस्सेदारी रखती है।

BANK 2019 PLUS PACK

ATTEMPT NOW

- राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत एनएचबी की स्थापना 9 जुलाई 1988 को की गई थी।
- NHB हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए नियामक है।

इसका उद्देश्य है-

- स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देना।
- ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना।
- आबादी के सभी क्षेत्रों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार की संभावनाओं को बढ़ावा देना।
- दक्षिण दास एनएचबी के वर्तमान एमडी और सीईओ हैं।
- इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है।

2. RBI जल्द जारी करेगा 20 रुपये का नया नोट

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) जल्द ही 20 रुपये का नया नोट जारी करेगा जिसमें अतिरिक्त फीचर्स शामिल होंगे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में 20 रुपये के बैंक नोट जारी करेगा, जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, श्री शक्तिकांता दास के हस्ताक्षर होंगे।
- पहले की श्रृंखला में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए 20 रुपये के सभी बैंक नोट कानूनी निविदा के रूप में जारी रहेंगे।

20 रुपये के बैंक नोट की विशेषताएं

- नोट का आधार रंग हरा-पीला है।
- बैंकनोट का आयाम 63 मिमी x 129 मिमी होगा।
- नए रुपये के बैंक नोट में देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए रिवर्स साइड पर एलोरा गुफाओं का रूपांकन है।

3. RBI ब्याज दर सुगमता चक्र शुरू करने वाला पहला एशिया-प्रशांत केंद्रीय बैंक बना: फिच

- फिच रेटिंग्स ने सूचित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एशिया-प्रशांत क्षेत्र (APAC) में पहला केंद्रीय बैंक बन गया है जिसने सौम्य खाद्य मुद्रास्फीति और आसान वैश्विक वित्तीय स्थिति के आधार पर ब्याज दर सहजता चक्र शुरू किया है।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में, सौम्य मुद्रास्फीति की संभावनाओं का हवाला देते हुए फरवरी और अप्रैल में दरों में कटौती की थी।
- 2019 के 4 महीनों में, RBI ने नीतिगत ब्याज दरों में 2 से 0.25% की कटौती की है, जो प्रत्येक के एक साल के निचले स्तर 6% पर है।
- यह 2016 में MPC के गठन के बाद से पहली बार की जाने वाली दर में कटौती है। 2.9% की दर पर मुद्रास्फीति RBI के 4% के कम्फर्ट क्षेत्र (+/- 2% के साथ) के भीतर रहा है। फिच की रिपोर्ट में कहा गया है कि RBI के लक्ष्यों के सापेक्ष राजकोषीय फिसलन राजकोषीय समेकन को रोक रहा है।

4. बैंकिंग लोकपाल ने वित्त वर्ष 18 में ग्राहकों की शिकायतों में 25% वृद्धि देखी: RBI

- RBI की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग लोकपाल को पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 18 में 24.9% अधिक ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुईं।
- बैंकिंग लोकपाल के 21 कार्यालयों ने वर्ष 2017-18 में 1,63,590 शिकायतें प्राप्त कीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24.9% की वृद्धि के साथ दर्ज की गईं।

- रिपोर्ट से पता चला कि वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का मुख्य आधार उचित प्रथा संहिता (22.1%) का गैर-अनुपालन, ए.टी.एम और डेबिट कार्ड के मुद्दे (15.1%), क्रेडिट कार्ड के मुद्दे (7.7%), प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफलता 6.8%), मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग (5.2%) थे।

नोट :

- बैंकिंग लोकपाल योजना (BO योजना) को 1995 में बैंकों के ग्राहकों के लिए लागत-मुक्त और शीघ्र शिकायत निवारण तंत्र के रूप में पेश किया गया था।

5. RBI, NBFCs लेने वाले गैर-जमाकर्ताओं के लिए लोकपाल योजना का विस्तार करता है

- भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी) को गैर-जमा लेने हेतु लोकपाल योजना की कवरेज को 100 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति का आकार दिया।
- यह योजना के तहत एन.बी.एफ.सी द्वारा सेवाओं में कमी से संबंधित एक लागत-मुक्त और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने में मदद करेगा।

नोट:

- लोकपाल योजना को पहले NBFC को स्वीकार करने वाली जमा राशि के लिए परिचालित किया गया था। अब, इसे एन.बी.एफ.सी की कुछ अन्य श्रेणियों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है।
- एन.बी.एफ.सी लोकपाल के कार्यालय चार मेट्रो केंद्रों अर्थात् चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में कार्य करते हैं तथा संबंधित क्षेत्रों में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करते हैं।

बैंकिंग एवं बीमा

6. सरकार ने इलाहाबाद बैंक की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपये की

- केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार - विमर्श के बाद बैंक की प्राधिकृत पूंजी 3,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपये कर दी है।
- अधिकृत पूंजी में वृद्धि से बैंक को अधिकतम धन जुटाने की सहूलियत होगी।
- सरकार ने इलाहाबाद बैंक की प्राधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपये कर दिया।

नोट:

- इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है।
- एसएस मल्लिकार्जुन राव इलाहाबाद बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ हैं।

7. कोटक बैंक ने NPCI के एपीआई प्लेटफॉर्म पर डेबिट कार्ड-आधारित ई-मैंडेट लॉन्च किया

- कोटक महिंद्रा बैंक (कोटक) ने एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ई-मैंडेट (इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट) एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस) प्लेटफॉर्म पर पहला डेबिट कार्ड-आधारित प्रमाणीकरण समाधान लॉन्च किया है।
- इसके साथ, यह नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड-आधारित ई-जनादेश प्रमाणीकरण दोनों के साथ लाइव होने वाला पहला गंतव्य बैंक बन गया है।

BANK 2019 PLUS PACK

ATTEMPT NOW

- इस पहल का उद्देश्य कोटक ग्राहकों को डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग प्रावधान के माध्यम से आधार + ओटीपी के साथ पूर्व e-NACH के समान, इलेक्ट्रॉनिक अधिदेश बनाने में सक्षम बनाना है।

नोट:

- कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ: उदय कोटक
- कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय: मुंबई.
- e-NACH: इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस
- OTP: वन टाइम पासवर्ड.

8. SBI ने लॉन्च किया ग्रीन कार लोन

- एसबीआई ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को ब्याज में 0.20 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है।
- ये इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी के लिए लॉन्च हुआ भारत का पहला ग्रीन कार लोन है।
- इस पहल का मकसद इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी को बढ़ावा देना है।
- SBI के ग्रीन कार लोन में 8 साल का रिपेमेंट पीरियड होगा
- SBI के सामान्य कार लोन में 7 साल का रिपेमेंट पीरियड होता है
- ग्रीन कार लोन लॉन्च होने के 6 महीने के भीतर SBI अपने ग्राहक से इस पर किसी भी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा

नोट:

- एसबीआई विप्रो के साथ मिलकर दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लॉन्च को बढ़ाने के लिए जलवायु समूह की ईवी 100 पहल में शामिल हुआ।
- एसबीआई ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए 2030 तक ईवीएस (इलेक्ट्रिक वाहन) में 100% प्रवासन को पहले ही अधिसूचित कर दिया है, इस प्रकार यह 2030 तक सड़क पर 30% ईवी सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिज्ञा के अनुरूप है।

9. जन धन बैंक खातों में जमा 1 लाख करोड़ रुपये को पार करेगी

- जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में कुल जमा राशि के जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपये के आकड़े को पार करने का अनुमान है।
- सरकारी डेटा ने दावा किया है कि मोदी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत 35.29 करोड़ खातों में संचयी संतुलन 3 अप्रैल को 97,665.66 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

नोट :

- सरकार ने 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई) शुरू की, जिसमें सार्वभौमिक बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- जन धन खाता धारकों में से आधे से अधिक महिलाएँ हैं, जबकि लगभग 59 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से हैं।
- सरकार ने योजना के तहत दुर्घटना बीमा कवर को 2018 में पहले 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया।
- जन धन में ओवरड्राफ्ट सीमा को सितंबर 2018 में दोगुनी अर्थात् 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया।
- सरकार ने अपना ध्यान बैंक से लेकर प्रत्येक परिवार तक प्रत्येक बैंक खाता रहित वयस्क पर केंद्रित किया।

BANK 2019 PLUS PACK

ATTEMPT NOW

- PMJDY का उद्देश्य विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, जरूरत-आधारित ऋण की पहुंच, प्रेषण सुविधा, कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों को बीमा और पेंशन सुनिश्चित करना है।

10. एसबीआई जनरल ने कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा बीमा शुरू किया

- एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने साइबर हमलों से कारोबारी इकाइयों की वित्तीय और साख से जुड़े नुकसान की बीमा-सुरक्षा के लिए उत्पाद पेश किया है।
- यह उत्पाद साइबर हमलों के बढ़ते खतरों से बचाव करेगा। इसे हैकिंग हमलों, पहचान की चोरी, संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने और कारोबार में व्यवधान जैसी गतिविधियों से रक्षा के लिए तैयार किया गया है।

11. बजाज आलियांज ने टोटल हेल्थ सिक्क्योर गोल प्लान लॉन्च किया

- बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने सहयोग में अपना पहला सहउत्पाद 'टोटल हेल्थ सिक्क्योर गोल' लॉन्च किया है।
- नया बीमा उत्पाद दो मौजूदा योजनाओं- बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के हेल्थ गार्ड पॉलिसी, और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के आईसिक्क्योर का संयोजन है
- हेल्थ गार्ड पॉलिसी के तहत, ग्राहक 1.5 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक की बीमा राशि के साथ सिल्वर या गोल्ड प्लान के बीच विकल्प चुन सकता है।

12. केनरा बैंक और केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ने लॉन्च किया 'वेबअश्योरेंस'

- केनरा बैंक और उसके जीवन बीमा साझेदार केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट के माध्यम से आसानी से जीवन बीमा खरीदने में सक्षम बनाने के लिए 'वेबअश्योरेंस' शुरू करने की घोषणा की है।
- केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस के चार जीवन बीमा उत्पादों को केनरा बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो कि ग्राहकों के बच्चों के भविष्य, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति योजना और सुरक्षा संबंधी प्रमुख जरूरतों को पूरा करेंगे।

नोट:

- केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों - केनरा बैंक (51 प्रतिशत) और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (23 प्रतिशत) और एचएसबीसी इंश्योरेंस होल्डिंग्स (26 प्रतिशत) के स्वामित्व वाली कंपनी है।

13. इंडसइंड बैंक ने भारत वित्तीय समावेशन के साथ विलय के लिए एनसीएलटी अनुमोदन प्राप्त किया - नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता इंडसइंड बैंक के भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन (BFIL) के साथ एक माइक्रोफाइनेंस कंपनी के विलय को मंजूरी दे दी है।

14. BuyUcoin ने थोक क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफार्म लॉन्च किया - BuyUcoin, जो भारत में दूसरा सबसे पुराना क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है, थोक क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के लिए एक नया और अनूठा मंच लॉन्च करने की घोषणा की जो अपने उपयोगकर्ताओं को कम कीमत में उतार-चढ़ाव के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करने की अनुमति देता है।

- मंच वर्तमान में मुक्त व्यापार मॉडल पर काम करता है यानी किसी भी व्यापार पर शून्य शुल्क लेता है।
- BuyUcoin द्वारा पेश किए गए इस नए फीचर से भारतीय बाजार में क्रिप्टोक्यूरेंसी की तरलता में सुधार करने और त्वरित लेनदेन, बेहतर कीमतों और बाजार में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी।

- मंच को ओटीसी (ओवर-द-काउंटर) डेस्क के रूप में जाना जाता है।
- यह उन व्यापारियों द्वारा पसंद किया जाता है जो थोक में क्रिप्टोक्यूरेंसी से निपटते हैं और व्यापार के दौरान बहुत अधिक उतार-चढ़ाव का विरोध करना चाहते हैं।

15. मेटलाइफ को फोर्ब्स की उद्घाटन ब्लॉकचेन 50 सूची में मान्यता दी गई

- एक बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनी मेटलाइफ को फोर्ब्स की उद्घाटन ब्लॉकचेन 50 सूची में नामित किया गया है, जो शीर्ष 50 संगठनों की पहली रैंकिंग है।
- कंपनी के अनुसार, मेटलाइफ को विटाना प्रयोग के लिए मान्यता दी गई, जिसे पिछले साल अगस्त में लुमेनलैब, मेटलाइफ के एशिया इनोवेशन सेंटर द्वारा सिंगापुर में लॉन्च किया गया था।
- सिंगापुर में पांच गर्भवती माताओं में से एक को प्रभावित करने वाली स्थिति में गर्भकालीन मधुमेह के मामले में गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला विटाना दुनिया का पहला, स्वचालित बीमा समाधान है।

नोट :

- मेटलाइफ एक बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।

समिति

16. सुरेश माथुर समिति - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने माइक्रो बीमा पर नियामक ढांचे की समीक्षा करने के लिए सुरेश माथुर समिति की स्थापना की और ऐसे उत्पादों की मांग बढ़ाने के उपायों की सिफारिश की।

- समिति का गठन उनके अंतर्निहित लाभों के बावजूद सूक्ष्म बीमा उत्पादों की कम-वांछित इच्छा की पृष्ठभूमि में किया गया है।

17. एन.सी.ए.पी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एन.वी मिन फॉर्म पैनल

- केंद्र ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को लागू करने और देश में वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) ने घोषणा की है कि समिति अपने सचिव सी.के. मिश्रा की अध्यक्षता में होगी, और इसके सदस्यों के रूप में दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश सहित 20 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक में एक मुख्य सचिव होगा।
- समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए NCAP के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समग्र मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करेगी।

18. CPWD ने भवन निर्माण हेतु डिजाइन नीति तैयार करने के लिए समिति का गठन किया

- सेंट्रल वर्क्स पब्लिक डिपार्टमेंट (CPWD) ने भवन निर्माण और बुनियादी ढांचा विकास के लिए एक डिजाइन नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
- सी.पी.डब्ल्यू.डी के अतिरिक्त महानिदेशक एम.के. शर्मा की अध्यक्षता में समिति का उद्देश्य सी.पी.डब्ल्यू.डी में सभी स्तरों पर भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास को पुनर्जीवित करना है जो आवास और शहरी मामला मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

नोट :

BANK 2019 PLUS PACK

ATTEMPT NOW

- सी.पी.डब्ल्यू.डी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी है।
- यह देश भर में सरकार की अधिकांश इमारतों का निर्माण करता है, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और अन्यों पर बाड़ लगाता है।
- यह एजेंसी भारत के साथ मैत्री कार्यक्रमों के तहत विदेशों में परियोजनाओं का संचालन भी करती है।

सर्वेक्षण/रिपोर्ट/सूचकांक

19. आई.आई.एम-बैंगलोर, क्यू.एस ई.एम.बी.ए रैंकिंग 2019 में केवल भारतीय संस्थान हैं

- IIM-बैंगलोर के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एंटरप्राइज़ मैनेजमेंट (PGPEM) को एशिया-प्रशांत क्षेत्र (APAC) में 12वीं और QS एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए रैंकिंग 2019 में वैश्विक स्तर पर 61वीं रैंक दी गई है।
- IIM-B भारत का एकमात्र B-School बन गया है, जो लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 100 B-Schools का हिस्सा है और APAC में शीर्ष 16 में है।

नोट :

- क्यू.एस रैंकिंग व्यक्तिगत विषय क्षेत्रों में दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों की पहचान करती है ताकि जो छात्र जानते हैं कि वे कौन से विषय में रुचि रखते हैं वे उपयुक्त विश्वविद्यालय पा सकते हैं।
- क्यू.एस एग्जीक्यूटिव एम.बी.ए रैंकिंग 2019 में कुछ मानकों के आधार पर बी-स्कूलों की रैंकिंग की गई है, जैसे विचार नेतृत्व, कार्यकारी प्रोफाइल, विविधता और कैरियर के परिणाम।
- एन.आई.आर.एफ (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क) रैंकिंग 2019 में, भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा।

20. कैंसर प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2019: भारत 19वें स्थान पर

- कैंसर प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स (आई.सी.पी) में भारत 28 देशों में से 19वें स्थान पर था।
- सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ई.आई.यू) द्वारा जारी किया जाता है।
- इसे EIU द्वारा तैयार "Cancer preparedness around the world: National readiness for a global epidemic" शीर्षक से रिपोर्ट के एक हिस्से के रूप में जारी किया गया था।
- शीर्ष 3 देश ऑस्ट्रेलिया (प्रथम), नीदरलैंड (दूसरे) और जर्मनी (तीसरे) हैं।
- निचले तीन देश सऊदी अरब (28वें), रोमानिया (27वें) और मिस्र (26वें) हैं।

21. 2018 में हैकर्स द्वारा दूसरा-सर्वाधिक लक्षित देश भारत: रिपोर्ट

- अकामाई टेक्नोलॉजीज रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में भारत को हैकर्स द्वारा दूसरे सबसे अधिक लक्षित देश के रूप में 120 करोड़ हमलों के साथ स्थान दिया गया था।
- अकामाई टेक्नोलॉजीज की रिपोर्ट बताती है कि 2018 में 120 करोड़ से अधिक खाता टेकओवर हमलों के साथ, भारत अमेरिका के बाद दुनिया में हैकिंग के प्रयासों के लिए दूसरे स्थान पर है।
- कनाडा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है।

अर्थव्यवस्था समाचार

22. सरकार ने गेहूं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया

- सरकार ने गेहूं पर सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है।
- इस कदम का मकसद आयात पर अंकुश लगाना और घरेलू उत्पादकों के हितों को संरक्षण प्रदान करना है।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना के जरिये गेहूं पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की घोषणा की है।
- सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1,840 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
- पिछले साल यह 1,735 रुपये प्रति क्विंटल था।
- एमएसपी वह कीमत होती है जिसपर सरकार किसानों से उनकी उपज की खरीद करती है।
- सरकार ने किसानों को उनकी उपज पर दिये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को उनकी उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना तय करने का फैसला किया है।

23. SEBI ने रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) और इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) योजनाओं में निवेश की न्यूनतम राशि घटा दी

- पूंजी बाजार नियामक संस्था SEBI ने रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) और इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) योजनाओं में निवेश की न्यूनतम राशि घटा दी है।
- इसके साथ ही निवेश के लिए यूनिट के लाट को परिभाषित किया है।
- रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के लिए REIT के माध्यम से पैसा जुटाया जाता है।
- REIT में निवेश की न्यूनतम राशि 50,000 रुपये रखनी होगी।
- इसी प्रकार InvITs के मामले में एक लॉट का न्यूनतम मूल्य एक लाख रुपये रखने को कहा गया है।

नोट:

- वर्तमान में रीट इश्यू में प्रारम्भिक पेशकश उसके बाद के ऑफर में किसी निवेशक से न्यूनतम आवेदन दो लाख रुपये से कम का नहीं होता है। इनविट के मामले में यह 10 लाख रुपये रखा गया है।

24. माइक्रोसॉफ्ट एक लाख करोड़ डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की चौथी और अमेरिका की तीसरी कंपनी बनी

- माइक्रोसॉफ्ट एक लाख करोड़ डॉलर (करीब 70 लाख करोड़ रुपए) मार्केट वैल्यू का आंकड़ा छूने वाली दुनिया की चौथी कंपनी बन गई है।
- चीन की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी पेट्रो चाइना यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है।
- सके बाद अमेरिकी टेक कंपनी एपल ऐसा करने वाली दूसरी और अमेजन तीसरी कंपनी बनी।

25. विप्रो ने फिलीपींस की सबसे बड़ी पर्सनल केयर कंपनी स्प्लैश कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण किया

- विप्रो कंज्यूमर केयर ने घोषणा की कि उसने फिलीपींस में स्थित एक व्यक्तिगत देखभाल कंपनी स्प्लैश कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- स्प्लैश सबसे बड़ा फिलिपिनो व्यक्तिगत देखभाल वाली कंपनी है और \$ 80 मिलियन के राजस्व के साथ उस बाजार में शीर्ष पांच में शामिल है।

BANK 2019 PLUS PACK

ATTEMPT NOW

- स्पलैश के अपने घरेलू आधार (देश) के बाहर बाजार हिस्सेदारी लगभग 15 प्रतिशत है।
- अधिग्रहण से पाँच बड़े बाजारों - इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, पश्चिम एशिया और नाइजीरिया में विप्रो की पैठ मजबूत हो गई है।

26. भारत की रेटिंग सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020 में 7.3% तक कम होने का अनुमान है

- भारत की रेटिंग और अनुसंधान ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2019-20 के राजकोषीय विकास को 7.3 प्रतिशत तक कम कर दिया, जिसका मुख्य कारण सामान्य मानसून की भविष्यवाणी और औद्योगिक उत्पादन में संवेग की हानि था।
- इससे पहले उसने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।

27. IEPF प्राधिकरण ने डिपॉजिटर्स मनी के 1514 करोड़ रुपये की वसूली की

- निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) प्राधिकरण ने कोलकाता स्थित पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी से 1,514 करोड़ रुपये की जमा राशि बरामद की है।
- जमाकर्ताओं का यह धन पिछले 15 वर्षों से कंपनी के पास लंबित था।

नोट :

- निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) की स्थापना केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत की थी।
- यह एक वैधानिक निकाय है जिसे कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है।
- कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय में सचिव IEPF के अध्यक्ष हैं।
- प्राधिकरण का उद्देश्य निवेशक की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष का प्रबंधन करना है।

28. दवा-प्रतिरोधी रोग 2050 तक एक वर्ष में 10 मिलियन तक मार सकता है: यू.एन

- एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध रिपोर्ट पर यूनाइटेड नेशन्स इंटरजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप (IACG) के अनुसार, दवा प्रतिरोधी रोग 2050 तक हर साल 10 मिलियन लोगों की मौत का कारण बन सकते हैं।
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध हर किसी के लिए, हर जगह एक खतरा है।
- वर्तमान में, ड्रग-प्रतिरोधी रोगों के कारण हर साल कम से कम 7,00,000 लोग मारे जाते हैं, जिनमें 2,30,000 लोग शामिल हैं, जो मल्टीड्रग-प्रतिरोधी तपेदिक से मरते हैं।
- WHO ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस सर्विलांस सिस्टम (GLASS) भारत सहित 71 देशों से डेटा एकत्र करता है, जिसमें एक तिहाई से अधिक देशों ने आम रोगजनकों के लिए व्यापक प्रतिरोध की सूचना दी।

29. 2018 में भारत में साइबर जोखिम बीमा की मांग 40% बढ़ी

- डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में भारत में साइबर जोखिम बीमा की मांग 40% बढ़ी है।
- रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय कॉर्पोरेट्स द्वारा 2018 में 350 साइबर बीमा पॉलिसियों को खरीदा गया था, जबकि 2017 में इन उत्पादों की बिक्री में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2016 और 2018 के बीच भारत साइबर खतरों से प्रभावित होने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था।

BANK 2019 PLUS PACK

ATTEMPT NOW

- ग्लोबल साइबर बीमा बाजार के 2017 में 4.2 बिलियन डॉलर से 2024 में 22.8 बिलियन डॉलर तक 27% के CAGR (कम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) पर बढ़ने की उम्मीद है।

30. भारत का 2022 तक 54.7 GW पवन क्षमता स्थापित करना : फिच सॉल्यूशंस

- फिच सॉल्यूशंस मैक्रो रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सरकार द्वारा निर्धारित 60-GW लक्ष्य के मुकाबले 2022 तक 54.7 GW पवन क्षमता स्थापित करने की संभावना है।
- देश ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर से 100 गीगावाॅट, हवा से 60 गीगावाॅट, जैव-ऊर्जा से 10 गीगावाॅट और छोटी पनबिजली से 5 गीगावाॅट शामिल है।

31. सरकार ने जी.एस.टी के तहत ई-चालान की शुरुआत की जांच करने हेतु समिति बनाई

- सरकार माल और सेवा कर (जी.एस.टी) पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक चालान (ई-चालान) की शुरुआत करने जा रही है, यह एक कदम है जो अगर लागू किया जाता है तो यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा और कर चोरी पर रोक लगाकर बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- जी.एस.टी नेटवर्क (जी.एस.टी.एन), केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों वाली 13 सदस्यीय समिति का गठन दक्षिण कोरिया, लैटिन अमेरिका और अन्य देशों के इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस सिस्टम की जांच करने और भारत के लिए एक मॉडल का सुझाव देने के लिए किया गया है।

32. चीन से दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध का विस्तार किया

- सरकार ने चाकलेट सहित दूध और उसके उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया, चीन से लेकर प्रयोगशालाओं तक जहरीले रासायनिक मेलामाइन की उपस्थिति के परीक्षण के लिए बंदरगाहों को अपग्रेड किया गया है।
- प्रतिबंध पहली बार सितंबर 2008 में लगाया गया था और बाद में इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है।

नोट :

- चीन की ओर से कुछ दूध की कनसाइनमेंट में मेलामाइन की मौजूदगी की आशंका पर प्रतिबंध लगाया गया था।
- मेलामाइन एक विषाक्त रसायन है जिसका उपयोग प्लास्टिक और उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है।

नोट:

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और दूध का उपभोक्ता है। यह सालाना लगभग 150 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है।
- उत्तर प्रदेश राजस्थान और गुजरात के बाद दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है।

समझौता

33. TCS ने देश की मेल वितरण प्रणाली को बदलने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

- भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने डाक विभाग के साथ मिलकर इसे बहु-सेवा डिजिटल हब में बदलने, मेल और पैकेजों के वितरण को आधुनिक बनाने, ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और अभिनव सेवाओं को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है।

34. .एस.ई अपने सदस्यों को सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिए नेटवर्क इंटेलिजेंस के साथ टाइ-अप करता है

BANK 2019 PLUS PACK

ATTEMPT NOW

- बी.एस.ई ने नेटवर्क इंटेलिजेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) में प्रवेश किया है, जो वैश्विक साइबर सुरक्षा सेवा प्रदाता है जो सेबी द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप अपने सदस्यों को साइबर सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करता है।
- नेटवर्क इंटेलिजेंस अपने स्वयं के विकसित प्लेटफॉर्म - ब्लूस्कोप का उपयोग कर सदस्यों को 24 × 7 साइबर सुरक्षा संचालन की पेशकश करेगा। इससे पहले, बी.एस.ई ने सेफ के उपयोग से सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टॉक ब्रोकरों को सुरक्षित करने के लिए जॉन चेंबर्स के समर्थित ल्यूसिडस के साथ भी संबंध स्थापित किया।

35. आयुष मंत्रालय ने सी.एस.आई.आर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

- आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) पर हस्ताक्षर किए।
- इससे पहले, सी.एस.आई.आर और आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टी.के.डी.एल) विकसित की है जो पारंपरिक ज्ञान की जैव-पाइरेसी और दुरुपयोग को रोकती है।

36. यूनिसेफ, नीति आयोग ने बच्चों के सशक्तीकरण के लिए टाइ-अप किया

- नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और यूनिसेफ इंडिया ने विभिन्न समुदायों में छोटे बच्चों के बीच भागीदारी, कौशल और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक खुला मंच प्रदान करने हेतु एक लेटर ऑफ इंटेन्ट (LoI) पर हस्ताक्षर किए।
- एक रिलीज के अनुसार, बाल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को उन्मुख करने के लिए अटल टिकरिंग लैब पहल के माध्यम से योजना को लागू किया जाएगा।

नोट:

- यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।

37. भारतीय सेना ने चीन, पाकिस्तान सीमाओं पर सुरंगों के निर्माण हेतु NHPC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

- भारतीय सेना ने गोला-बारूद और अन्य युद्ध से संबंधित उपकरणों के भंडारण के लिए चीन और पाकिस्तान सीमाओं के साथ चार भूमिगत सुरंगों का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम (NHPC) लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए।
- तीन सुरंग चीनी सीमा के साथ बनाई जाएंगी और एक सुरंग पाकिस्तान सीमा के साथ बनाई जाएगी। यह सुरंग 175-200 मीट्रिक टन गोला बारूद का भंडारण कर सकती है और इस पायलट परियोजना की लागत लगभग 15 करोड़ रुपये है।

शिखर सम्मेलन

38. नेपाल में जलवायु क्रिया और आपदा तैयारी पर ABU मीडिया शिखर सम्मेलन

- काठमांडू में आयोजित 5वीं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू) मीडिया समिट ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस।
- दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय “Media Solutions for Sustainable Future: Saving Lives, Building Resilient Communities” था।
- शिखर सम्मेलन का मूल उद्देश्य जलवायु कार्रवाई और आपदा तैयारियों में तेजी लाने के लिए मीडिया की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने तथा सहयोग और संयुक्त व्यावहारिक परियोजनाओं के लिए मीडिया पेशेवरों के लिए हितधारकों को जोड़ने के मुद्दे को संबोधित करना है।

39. चीन ने बीजिंग में दूसरी बेल्ट एंड रोड फोरम की मेजबानी की

- बेल्ट एंड रोड फोरम (BRF) का दूसरा संस्करण चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया था, जिसमें 37 देशों के प्रमुख और 159 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रमुख (आई.एम.एफ) क्रिस्टीन लेगार्ड के साथ भाग लिया।
- इस आयोजन का विषय “Belt and Road Cooperation: Shaping a Brighter Shared Future” था। बेल्ट एंड रोड फोरम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक हिस्सा है। BRI के विचार को सबसे पहले 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रस्तावित किया था।

Banking & Economy Terminology

40. NCLT - National Company Law Tribunal
41. OTC - Over-the-counter
42. NCAP - National Clean Air Programme
43. REITs - Real Estate Investment Trusts
44. InvITs - Infrastructure Investment Trusts
45. IEPF - Investor Education and Protection Fund

_____X_____X_____X_____X_____

BANK 2019 PLUS PACK

ATTEMPT NOW

BANK 2019 PLUS PACK

1. 400+ Mock Tests on the Latest Exam Pattern
2. Available in Hindi & English
3. All India Rank & Performance Analysis
4. Detailed Explanation of Solutions
5. Topic-wise Tests & Video Courses
6. Available on Mobile & Desktop

